



1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Jaipur  
 2. Member Secretary, Central Empowered Committee (CEC), New Delhi  
 3. The Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Jaipur  
 4. The Regional Office (I. O.), New Delhi  
 5. User Agency i.e. National Highway Authority of India  
 6. Monitoring Cell, Ministry of Environment and Forests  
 7. Guard File.

(A. K. Joshi)  
 Assistant Inspector (General of Forests)

Copy to:

After receipt of the compliance report on the fulfillment of the above mentioned conditions. No. (1) in (XX) of Para 2 above from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section-1 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The transfer of forest land to the User Agency shall not be affected by the State Government till formal orders approving the diversion of forest land are issued by the Central Government.

- VIII. The User Agency shall provide a noise barrier on the bridge and 400 m. on either side of the Chambal River.
- IX. Stone masonry wall of 2.5 m high along with one meter fence shall be provided on either side to act as a barrier between the human settlement and wildlife.
- X. No construction workshop shall be set up upto 2 kms of sanctuary area, and wherever possible prefabricated structures be erected.
- XI. No labour camps shall be situated in the forest area. The User Agency shall provide fuel-wood preferably alternate fuel to the labourers working at the site to avoid damage/felling of trees.
- XII. Wherever blasting is essential, it shall be controlled and the latest method of slow burned blasting be followed.
- XIII. Silence zone shall be declared well before and after the sanctuary upto a considerable distance. Adequate signages be displayed for the purpose.
- XIV. The area falling between Kota-Jhalawar road and Chambal River shall be preserved as a green belt to the Kota city. Similarly, the forest land existing north of the bypass between Kota-Jhalawar road and Chambal River shall be preserved as a green belt to the Kota city.
- XV. The cost of permanent fencing and developing the green belt to the Kota city, one kilometre of the bypass road on forest land shall be included in the cost of bypass project apart from the Compensatory Afforestation and other costs.
- XVI. The cost of permanent fencing along the Kota-Rawatbaha road and the Kota Jawahar Sagar road each for a distance of 5 kms shall be included in the project cost to ensure that no encroachments take place undertaken by the Forest Department, Rajasthan in consultation with the Wildlife Institute of India prior to the construction phase and after the construction phase so that necessary monitoring and maintenance corrective measures can be adopted. The cost in this regard should be borne by the User Agency.
- XVII. Rapid assessment of the status of the wildlife from Kota Barrage to Jawahar Sagar Dam shall be undertaken by the Forest Department, Rajasthan while forwarding the above proposals to the Central Government, and conditions stipulated by the State Government of Rajasthan while forwarding the above proposals to the Central Government, as approved by the Hon'ble Supreme Court in its Order dated 31.12.2006, in LA No 1626-1627 in Writ Petition (C) 202 of 1995, shall be adhered to by the User Agency.
- XIX. The 902 ha forest area as detailed in Alignment No. 2 by-pass, shall be developed as an urban managed wildlife conservation area for the purpose of wildlife conservation and environmental education.
- XX. All other conditions stipulated by the State Government of Rajasthan while forwarding the above proposals to the Central Government, as approved by the Hon'ble Supreme Court in its Order dated 31.12.2006, in LA No 1626-1627 in Writ Petition (C) 202 of 1995, shall be adhered to by the User Agency.

(A. K. Joshi)  
 Assistant Inspector (General of Forests)

Copy to:



आति प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 प्रादेशिक एवं नोजल अधिकारी  
 एकसौर राजा जयपुर।

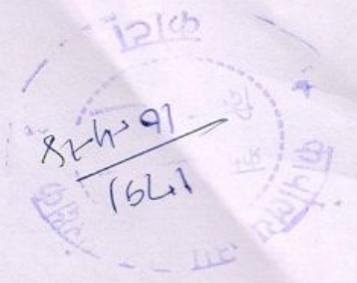
विषय :- Land For Extension of Bhamashah Krishi Upari Mandi Simiti  
 (FP/RJ/Other/20036/2016)  
 उप वन संरक्षक कोटा का पत्र संख्या एक (उपसं/तक)  
 /2018/2826 दिनांक 02.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि उप वन संरक्षक कोटा ने प्रासंगिक पत्र से कृषि  
 उपज मण्डल समिति द्वारा एन.एच.-76 बाई पास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी 96  
 हेक्टर वनभूमि के बारे में मौके की स्थिति से संबंधित विन्युअर्स पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत  
 की गई है:-

कृषि उपज मण्डल समिति द्वारा एन.एच.-76 बाईपास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई 96  
 हेक्टर वनभूमि के प्रस्ताव (भामाशाह मण्डल के प्रस्ताव) का अध्ययन किया गया। संश्लेषण संवर्धन  
 के अन्तर्गत 4000 पौधे लगाये गये हैं, जहाँ पौधे लगाये गये हैं वह वनभूमि भामाशाह मण्डल विस्तार  
 हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया।  
 निरीक्षण रिपोर्ट में अगत करया कि उक्त स्थल एन.एच. 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण में एक  
 सी.ए. के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक  
 स्वीकृति की शर्तों में शर्त सं. 5 के अनुसार इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना है। उप वन  
 संरक्षक कोटा द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अगत करया है कि, माननीय उच्च न्यायालय के  
 निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन  
 06.07.2017 में आवश्यक संसाधित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन

किया जाना उचित होगा।  
 मौके पर सीको द्वारा 47 हेक्टर वनक्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने पर उप वन संरक्षक कोटा  
 को कार्यवाही किये जाने के निर्देश इस कार्यालय द्वारा दिये गये हैं। इस संबंध में उप वन संरक्षक  
 कोटा ने अगत करया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाहपुरा से अतिक्रमण के संबंध में जानकारी चाही  
 जाने पर क्षेत्रीय लाहपुरा द्वारा पत्रांक 1691 दिनांक 23.03.2018 से अगत करया गया कि, उक्त  
 वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तत्समय क्षेत्रीय वन अधिकारी लाहपुरा द्वारा रिको कोटा के  
 विरुद्ध विभागीय एक.आर्.आर. 56-09 दिनांक 19.09.1996 दर्ज की गई थी। इस एक.आर्.आर. में  
 आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।



प्रयोगकर्ता आभार माग्याह कृषि उपज मण्डी समिति ने विस्तार हेतु पूर्व में 74 हैक्टर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्तावित साइट का मौका निरीक्षण करने एवं रिकॉर्ड देखने पर पाया गया कि, वर्तमान में स्थापित कृषि उपज मण्डी में 22 हैक्टर वन भूमि पूर्व से ही सम्मिलित है। प्रयोगकर्ता आभार माग्याह कोटा द्वारा वर्तमान में कृषि उपज मण्डी में स्थित वन भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक 14.08.2017 को इस कार्यालय द्वारा EDS जारी किया गया। तदुपरांत प्रयोगकर्ता आभार माग्याह कृषि उपज मण्डी विस्तार हेतु उपरोक्त 96 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव को अंतिम करना उचित होगा।

कमांक:एक13(वन संरक्षण)/संभुवस/2018/ 2878 दिनांक : 6/9/2018  
प्रतिनिधि उप वन संरक्षक कोटा को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार दी जाकर लेख है कि प्रयोगकर्ता आभार माग्याह कृषि उपज मण्डी समिति के विस्तार के लिए 96 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव में एनएचओ 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर निर्माण की शर्त में 5 में संशोधन होने पर ही प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च कार्यालय को अंतिम किया जा सकता।

(इन्द्रज सिंह)  
अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

(इन्द्रज सिंह)  
अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

भवदीय

Handwritten signature and date: 9/11/2018